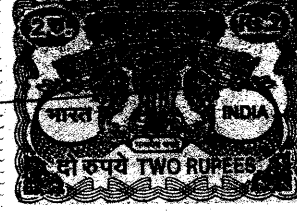
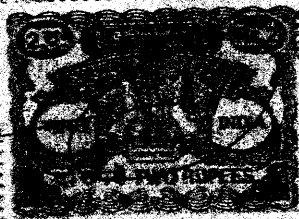


R-5130-16



R-5130-16

शंकर प्रसाद पाण्डेय तनय श्री मोतीलाल पाण्डेय, निवासी ग्राम धवैया, 291, तह०-मनगवां, पोस्ट रघुराजगढ़, जिला रीवा (म०प्र०)

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

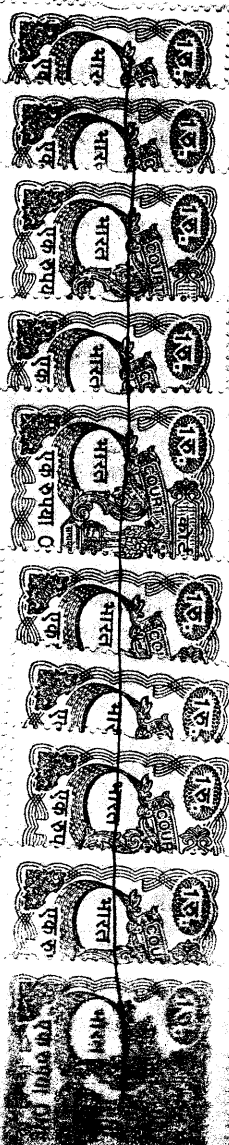
- 1- प्रद्युम्न प्रसाद तिवारी तनय श्री इन्द्रभान प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम खुरहा, तह०-रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2- म०प्र० शासन

गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई० विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार, तह०-रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०) दिनांक 14/09/2012 जो राजस्व प्रकरण क्र०-5 अ-12/2011-12 में पारित

श्री. प्रियप्रसाद द्विवेदी एडवोकेट
द्वारा आज दिनांक 10-3-16 के प्रस्तुत किया गया।

सिद्धांत
सिद्धांत कोर्ट सेवा



मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14/09/2012 सर्वथा विधि विधान एवं मौके की स्थिति के विपरीत है, जो कि आवेदक भूमि नं०-32, 33, 34, 35, 36 व 37 स्थित ग्राम धवैया का भूमिस्वामी है और उसी के बगल में ग्राम खुरहा की स्थित भूमि 336, 382, 383 का अनावेदक भूमिस्वामी है, इस तरह दोनों ही पक्षकार अगल-बगल की जमीनों के सरहदी काश्तकार है, ऐसी स्थिति में विधिवत सूचना देकर ही सीमांकन की कार्यवाही करना चाहिए था।

R/5130

श्री. प्रसाद द्विवेदी

- २ -
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5130-दो/2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१ -02-2017	<p style="text-align: center;">आवेदक अधिवक्ता श्री आर०एस० सेंगर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर किया।</p> <p>2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5/अ-12/11-12 आदेश दिनांक 14-9-12 के विरुद्ध निगरानी पेश की गई है। अनावेदक के द्वारा भूमि नं० 336, 382, 383 के सीमांकन के लिए आवेदन पेश किया और सीमांकन करवाया, लेकिन म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 129 में निर्मित नियमों का अनुसरण नहीं किया।</p> <p>म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में यह वर्णित है कि हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण में संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा सीमांक दिनांक 11-6-2011 को किया गया। इन्होंने अपने शपथ पत्र में भी अपने पद एवं हल्का का वर्णन किया है, जिसकी प्रति संलग्न है। फील्डबुक, पंचनामा पटवारी द्वारा ही बनाये गये हैं। संहिता की धारा 129 में यह प्रावधान है कि-</p> <p>“तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्याक की या उपखण्ड या भू-खण्ड की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा, और उस पर सीमाचिन्ह सनिर्मित कर सकेगा,</p> <p>उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सीमांकन कर सीमाचिन्ह</p>	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

तहसीलदार या अन्य नियमित राजस्व अधिकारी द्वारा ही निर्मित किये जा सकते हैं। पटवारी राजस्व अधिकारी नहीं है। इसका कारण पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन अधिकारिता रहित है। अतः अनावेदक द्वारा कराया गया सीमांकन विधि के विपरीत है तथा निरस्त करने योग्य है।

आवेदक सरहदी काश्तकार है, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन के विरुद्ध आवेदक ने अधिनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार) के समक्ष आपत्ति पेश की थी, तत्पश्चात अनावेदक के सीमांकन को निरस्त करते हुये पुनः सीमांकन का आदेश दिनांक 24-10-2011 को न्यायालय द्वारा दिया गया। अनावेदक द्वारा इसके विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी दायर की गई। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 के तहत कलेक्टर/अपर कलेक्टर को निगरानी की अधिकारिता समाप्त की गई है। आदेश दिनांक 24-10-2011 के विरुद्ध अपर कलेक्टर ने 14-8-12 को अधिनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार) को प्रकरण उभय पक्षों की सुवाई हेतु भूजा गया, जिसकी निगरानी इस माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक शंकर प्रसाद पांडे पिता मोतीलाल विरुद्ध प्रद्युम्न तिवारी के नाम से लंबित है। जिसका प्रकरण क्रमांक 3350-दो/12 है। चूंकि सीमांकन प्रकरण की निगरानी है तथा सभी दस्तावेज संलग्न है ऐसी स्थिति में गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाता है।

अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन 11-6-11 के फील्डबुक में स्पष्ट रूप से वर्णित है की आवेदक

P. J. A.

M.

की भूमि नं0 37 जो एक मेड है और धवैया गाम दक्षिण छोर की अंतिम सीमा में है। तीन पेड आम जो कम से कम 30-35 वर्ष से अधिक के लगाए गये है। जो मोतीलाल पाण्डेय द्वारा लगाये गये है तथा 40-45 वर्ष से अधिक का कब्जा भी इनका है। यह लेख अपने आप में साबित करता है की आवेदक द्वारा कराया गया सीमांकन सही और विधि के अनुरूप है और अनावेदक द्वारा कराया गया सीमांकन सही और विधि के अनुरूप है और अनावेदक द्वारा कराया गया सीमांकन गलत और निरस्त करने योग्य है।

3/ आवेदक ने अपनी भूमि नं0 32, 33, 34, 35, 36, 37 का विधिपूर्व दोनों ग्राम धवैया और खरहा के पटवारी और राजस्व निरीक्षक की टीम गठित कर सीमांकन 2008 राजस्व प्रकरण कमांक 31/अ-12/2007-08 को कराया जिसकी पुष्टि निर्विवाद बिना आपत्ति की दिनांक 23-5-2008 को हुई। फिर आवेदक ने अपने अपनी इन्ही भूमियों का सीमांकन विधिपूर्वक टीम गठित करवा कर 2014 में प्रकरण कमांक की श्रेणी अ-12 में करवाया, जिसकी पुष्टि दिनांक 15-4-2014 को बिना आपत्ति विवाद के हो गई। इस आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं होने से वह अंतिम हो गया।

अधीनस्थ न्यायालय में अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश दिांक 14-8-12 का पालन अनावेदक के सीमांकन के अंतर्गत नहीं किया गया और सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 11-6-11 को दिया गया जो कि अधिकार विहीन था क्योंकि इसे तहसीलदार रायपुर कर्चुचिलयान ने दिनांक 24-10-11 को निरस्त कर

P/S

AM

दिया था। इसके बाद प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष गया तत्पश्चात पुनः वापस तहसील को प्राप्त हुआ, लेकिन पुनः सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं की गई और दिनांक 14-9-12 को अदेश पारित किया गया जो कि कायम रखने योग्य नहीं है। आवेदक ने अपने भूमियों को दो बार 2008 और 2014 सीमांकन करवा चुका है जो आपस में मेल करती है और विधि एवं तर्कसंगत है तथा मौके में अपनी भूमि का काबिज है। फलतः निगरानी को बल मिलता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14-9-12 निरस्त किया जाता है तथा इसके अग्रिम धारा 250 की कार्यवाही भी निरस्त की जाती है। प्रकरण नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को यह निर्देश दिये जाते हैं प्रकरण में सीमांकन दल गठित कर आवेदक एवं अनावेदक दोनों को विधिवत सूचना देने के उपरांत उनकी उपस्थिति में दोनों पक्षों की भूमि का एकसाथ विधिव सीमांकन करें। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


सदस्य

